

४. सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन

एक स्थानीय समाचारपत्र का यह समाचार पढ़िए ।

बाल विवाह विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली है । अब बाल विवाहों में ५०% की कमी आई है । इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सजगता से काम किया है ।

दहेज विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी सहायता की है । अब इसी क्षेत्र में कुपोषण विरोधी अभियान शुरू करना आवश्यक है क्योंकि निर्धनता और कुपोषण; ये अधिक ध्यान देने योग्य समस्याएँ हैं ।

- समाचारपत्र के इस समाचार में आंदोलनों का उल्लेख हुआ है । क्या आप उसका अर्थ बता सकते हैं ?
- इस समाचार में प्रत्येक विषय स्वतंत्र दिखाई देता है । अर्थात् क्या सभी आंदोलन एक ही विषय से संबंधित होते हैं ?
- क्या आपको ऐसा लगता है कि आंदोलनों के परस्पर एक-दूसरे को सहयोग करने से वे प्रभावी एवं सफल होंगे ?

पिछले पाठ में हमने राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त की । राजनीतिक दल सत्ता की प्रतिद्वंद्विता में रहते हैं और चुनाव में सफलता प्राप्त कर वे सामान्य लोगों के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं । राजनीतिक दलों की भूमिका सर्वसमावेशक होती है । वे किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते । सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक के सभी विषयों पर राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर निर्णय लेने पड़ते हैं । समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के लिए राजनीतिक दलों के पास विशिष्ट कार्यक्रम होना आवश्यक है । किसान,

श्रमिक, उद्यमी, महिला, युवा वर्ग और वरिष्ठ नागरिक आदि सभी का विचार करके राजनीतिक दल अपनी नीतियाँ निर्धारित करते हैं ।

आंदोलन क्यों ?

समाज के सभी लोगों को राजनीतिक दलों में सम्मिलित होकर सार्वजनिक हितों के लिए कुछ करना संभव नहीं होता । कुछ लोग किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं । उस समस्या को हल करने के लिए लोगों को संगठित कर सरकार पर एकाध कृति करने के लिए दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं । निरंतर कृतिशील रहकर उस समस्या के बारे में जनमत तैयार करके राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालने का काम किया जाता है । इन सामूहिक कृतियों को 'आंदोलन' कहा जाता है । सामूहिक कृति आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है ।

लोकतंत्र में आंदोलनों का बड़ा महत्त्व होता है । आंदोलनों के माध्यम से कई सार्वजनिक प्रश्न चर्चा में आते हैं । सरकार को भी इन प्रश्नों पर गंभीरता से सोचना पड़ता है । आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार को उस समस्या से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है । अपनी नीतियाँ निर्धारित करते समय सरकार को इस जानकारी का उपयोग होता है ।

कभी-कभी सरकार के कुछ निर्णयों या नीतियों का विरोध करने के लिए भी आंदोलन होते हैं ।



बताइए तो ?

विस्थापितों का पुनर्वसन सही ढंग से हो, उनकी आजीविका का साधन सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारे देश में कौन-से सक्रिय आंदोलन हुए ?

निषेध अथवा विरोध करने का अधिकार (Right to protest) लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अधिकार है परंतु उसका बहुत ही संयम और दायित्व के साथ उपयोग करना चाहिए।

आंदोलन का अर्थ क्या है ?

- आंदोलन एक सामूहिक कृति है। उसमें कई लोगों का सक्रिय सहभाग अपेक्षित रहता है।
- आंदोलन किसी विशेष समस्या पर लोगों द्वारा निर्मित संगठन होता है। जैसे- 'प्रदूषण' इस एक ही समस्या को लेकर आंदोलन खड़ा हो सकता है।
- प्रत्येक आंदोलन का कोई निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य अथवा समस्या होती है। जैसे- भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार को नष्ट करना होता है।
- आंदोलन का नेतृत्व होता है। नेतृत्व के कारण आंदोलन क्रियाशील रहता है। आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम और आंदोलनात्मक नीति के संदर्भ में निर्णय लिये जाते हैं। यदि आंदोलन का नेतृत्व दृढ़ हो तो आंदोलन परिणामकारक होता है।

• आंदोलनों के कई संगठन होते हैं। संगठनों के बिना आंदोलन समस्याओं को निरंतर आगे नहीं बढ़ा सकता। जैसे- किसानों के आंदोलन के लिए किसान संगठन काम करता है।

• किसी भी आंदोलन को जनता का समर्थन मिलना आवश्यक होता है। जिस समस्या को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ है, वह समस्या जनता को अपनी समस्या महसूस होनी चाहिए। उसके लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है। तत्पश्चात उसके अनुसार जनमत बनाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं।

चर्चा कीजिए -

यद्यपि आंदोलन किसी एक समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करते हों, फिर भी उन आंदोलनों के पीछे एक व्यापक विचारधारा होती है। जैसे- बालविवाह अथवा दहेजबंदी आंदोलनों का लोकतंत्र, महिलाओं का सक्षमीकरण, सामाजिक समता आदि मूल्यों पर विश्वास होता है। कुछ आंदोलनों का यथासमय राजनीतिक दलों में परिवर्तन होता है।

निम्न संवाद पढ़िए और उसपर एक परिच्छेद लिखिए।





ढूढे तो ?

- भारत में किन आंदोलनों के कारण न्यायालयों में जनहित याचिकाएँ प्रविष्ट हुईं और न्यायालयों को उनपर निर्णय देना पड़ा ?
- महात्मा फुले, महात्मा गांधी, संत गाडगे महाराज, डॉ.बाबासाहब आंबेडकर ने कौन-कौन-से आंदोलन चलाए ?

चर्चा कीजिए ।

भारत में भूमिपुत्रों के आंदोलन किन मुद्दों के प्रति आग्रही हैं ?



करके देखें-

अंधश्रद्धा उन्मूलन आंदोलन, नदियों के प्रदूषण की रोक-थाम के लिए हुए आंदोलन, स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी आंदोलन, 'नॉट इन माई नेम' आदि आंदोलनों से संबंधित समाचारपत्रों में छपे समाचारों का संग्रह कीजिए ।



क्या, आप जानते हैं ?

- सार्वजनिक समस्याएँ केवल सामाजिक क्षेत्र से ही संबंधित होती हैं, ऐसा नहीं है । वे समाज के किसी भी क्षेत्र से उत्पन्न हो सकती हैं । समाज सुधार के लिए अपने देश में और विशेषतः महाराष्ट्र में कई आंदोलन हुए और उन्हीं आंदोलनों के फलस्वरूप समाज के आधुनिक होने की शुरुआत हुई ।
- हमारा स्वतंत्रता युद्ध भी एक सामाजिक आंदोलन ही था ।
- राजनीतिक और आर्थिक आंदोलनों द्वारा नागरिकों के अधिकारों का संवर्धन, मताधिकार, न्यूनतम वेतन, वित्तीय सुरक्षा आदि समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है । स्वदेशी भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय आंदोलन है ।

भारत के प्रमुख आंदोलन



बिरसा मुंडा

आदिवासी आंदोलन :

स्वतंत्रतापूर्व समय में अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों की वन संपत्ति पर आजीविका करने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की । जिसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र के कोलाम, ओडिशा

के गोंड, महाराष्ट्र के कोली, भील, पिंडारी और बिहार के संथाल, मुंडा आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसके विरोध में विद्रोह किया । तब से आदिवासियों का संघर्ष जारी है । भारत में आदिवासियों की कई समस्याएँ हैं । उनमें सबसे प्रमुख समस्या उनका जंगलों पर जो अधिकार है; उसे नकारा जाना है । आदिवासी आंदोलन की प्रमुख माँग आदिवासियों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया जाना है । वनों के उत्पादों को इकट्ठा करने और वनभूमि पर वृक्षों को लगाने का अधिकार उन्हें मिले ।

भारत का किसान आंदोलन : भारत का किसान आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है । अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शासन में सरकार की कृषिविरोधी नीतियों के कारण किसान संगठित होने लगे । बारडोली, चंपारण्य, खोती की समस्याओं को लेकर हुए किसान आंदोलनों के बारे में आपको जानकारी होगी ही । किसान आंदोलनों के लिए महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रानडे और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा ली जाती है ।

कृषि के संबंध में हुए कुछ सुधारों के (उदा., चकबंदी अधिनियम, भूमि कानून आदि) कारण किसान आंदोलन की गति धीमी हुई लेकिन हरितक्रांति के बाद किसान आंदोलन और अधिक क्रियाशील और परिणामकारी होने लगा । खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए और देश को अनाज के

मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरितक्रांति की गई परंतु उसका निर्धन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों में निर्धन और संपन्न किसान ऐसे दो वर्ग बन गए। उनमें असंतोष बढ़ गया और किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ।

कृषि उपज को सही दाम मिले, खेती को उद्योग का दर्जा मिले, स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकारा जाए, कर्जमाफी, ऋणमुक्ति और राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीति आदि किसान संगठनों की प्रमुख मांगें हैं।

किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आदि भारत के कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं।



करके देखें-

किसानों और खेतिहर मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किन योजनाओं को अमल में लाया गया है?

श्रमिक आंदोलन : भारत के श्रमिक आंदोलन को औद्योगीकरण की पार्श्वभूमि रही है। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियाँ जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई। १८९९ ई. में रेल मजदूरों ने अपनी माँगों के लिए हड़ताल की थी। श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए १९२० ई. में व्यापक संगठन की स्थापना हुई। यह संगठन 'ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस' के नाम से जाना जाता है।

स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा। १९६० ई. और ७० ई. के दशक में कई श्रमिक आंदोलन हुए।



करके देखें-

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात के समय में श्रमिकों से संबंधित जो कानून पारित हुए; उनकी जानकारी अंतरजाल की सहायता से प्राप्त कीजिए।

परंतु १९८० ई. से श्रमिक आंदोलन बिखर गया। पूरे देश में श्रमिकों के नए प्रश्न उभरकर आए हैं। वैश्वीकरण का भी श्रमिक आंदोलन पर परिणाम हुआ। अस्थिर रोजगार, ठेकादारी मजदूर, वित्तीय असुरक्षा, श्रमिक कानूनों का संरक्षण न मिलना, काम करने का निश्चित समयावधि न होना, काम की जगह पर असुरक्षितता, अस्वास्थ्य आदि आज के श्रमिक आंदोलन के सम्मुख निम्न समस्याएँ हैं।

स्त्री आंदोलन : स्वतंत्रतापूर्व काल में भारत में



सावित्रीबाई फुले

स्त्री आंदोलन की शुरुआत प्रगतिशील पुरुषों के नेतृत्व में हुई। स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, उनके शोषण की रोक-थाम होकर उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए तथा वे सार्वजनिक जीवन में सहभागी हो सकें; इसके लिए

अनेक सुधार आंदोलन हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, महात्मा जोतीराव फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे आदि की अगुवाई से सती प्रथा को विरोध, विधवा का पुनर्विवाह, स्त्रीशिक्षा, बाल विवाह को विरोध, स्त्रियों को मतदान का अधिकार



रमाबाई रानडे

जैसे कई सुधार हो सके। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों को सभी प्रकार के समान अधिकार प्रदान किए गए। फिर भी कई क्षेत्रों में स्त्रियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। स्त्री स्वतंत्रता समकालीन स्त्रियों के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मनुष्य के रूप में अधिकार मिले; इसके लिए वर्तमान समय में स्त्री आंदोलन हुआ था। स्त्री स्वतंत्रता यह भी इसके पीछे एक प्रमुख उद्देश्य था।

भारत में भ्रष्टाचार, जातिव्यवस्था का विरोध,

कट्टर धार्मिकता का विरोध जैसी समस्याओं के विरोध में आंदोलनों की शुरूआत हुई। इन आंदोलनों में स्त्रियाँ बड़े पैमाने में सहभागी हुईं। इनके द्वारा स्त्रियों को अपने पर होनेवाले अन्याय का बोध हुआ। स्त्रियों के नेतृत्व में स्त्री आंदोलन की शुरूआत हुई। भारतीय स्त्री आंदोलन में एकता नहीं है परंतु स्त्री संगठन स्त्री-स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सक्षमीकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर विविध स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा और मनुष्य के रूप में दर्जा तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आग्रह; यही स्त्री आंदोलन के सामने आज बड़ी चुनौती है।

पर्यावरण आंदोलन : पर्यावरण का होने वाला हास यह वर्तमान समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय



डॉ. राजेंद्र सिंह

भारत के जल पुरुष नाम से विख्यात डॉ. राजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान में बड़ी जलक्रांति की है। राजस्थान में हजारों 'जोहड़' (नदी पर बनाए गए मिट्टी के बाँध) निर्माण करने के माध्यम से वे लोकप्रिय बने। सिंह जी ने राजस्थान की मरुभूमि में नदियों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने 'तरुण भारत संघ' इस संगठन की स्थापना करके सैकड़ों गाँवों में लगभग ग्यारह हजार जोहड़ बनवाए। पूरे देश में पदयात्रा करके जल संवर्धन, नदियों को पुनर्जीवित करना, वन संवर्धन, वन्यजीव संवर्धन अभियान चलाए। पिछले ३१ वर्षों से उनका यह सामाजिक आंदोलन चल रहा है। पानी का नोबल पुरस्कार समझे जाने वाले 'स्टॉकहोम वॉटर प्राइज' पुरस्कार से डॉ. राजेंद्र सिंह सम्मानित हो चुके हैं।



पर्यावरण रक्षण

स्तर पर एक गंभीर समस्या है; यह हम जानते ही हैं। पर्यावरण का हास रोकने के लिए विश्व स्तर पर कई आंदोलन चल रहे हैं और इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सहयोग भी बड़ी मात्रा में मिल रहा है।

भारत में भी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों को महत्त्व देते हुए कई आंदोलन चल रहे हैं। जैवविविधता की रक्षा, पानी के विभिन्न स्रोतों का संवर्धन, जंगलावरण, नदियों का प्रदूषण, हरितक्षेत्र की रक्षा, रासायनिक द्रव्यों का उपयोग और उनके दुष्परिणाम आदि समस्याओं को लेकर विभिन्न आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं।

उपभोक्ता आंदोलन : १९८६ ई. में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य बड़ा व्यापक है। समाज का प्रत्येक घटक उपभोक्ता होता है। वित्त व्यवस्था और समाज



व्यवस्था में होने वाले बदलावों का प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उन्हें कई समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है। जैसे मिलावट, वस्तुओं के बढ़ाए गए दाम, तैल में होनेवाली धोखाधड़ी आदि। इस प्रकार की धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ।

आंदोलन के कारण नागरिकों की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता बढ़ती है। १९८० ई. के बाद

जो आंदोलन हुए, उन्हें 'नवसामाजिक आंदोलन' कहा जाता है क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ववर्ती आंदोलनों से भिन्न है। ये आंदोलन अधिकाधिक विषयनिष्ठ होने लगे हैं; अर्थात् प्रत्येक विषय को

लेकर जनआंदोलन बनाए जा रहे हैं।

अगले पाठ में हम लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों का अध्ययन करेंगे।



स्वाध्याय

१. निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

- (१) किसान आंदोलन की यह प्रमुख माँग है।
 (अ) वनभूमि पर वृक्ष लगाने का अधिकार मिले।
 (ब) कृषि उपज को सही दाम मिले।
 (क) उपभोक्ताओं का संरक्षण करना।
 (ड) बाँधों का निर्माण करना।
- (२) खेती का उत्पादन बढ़ाने और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए की गई।
 (अ) जल क्रांति (ब) हरित क्रांति
 (क) औद्योगिक क्रांति (ड) धवल क्रांति

२. अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए।

- (१) आदिवासी आंदोलन
- (२) श्रमिक आंदोलन

३. निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए।

- (१) पर्यावरण आंदोलन का कार्य स्पष्ट कीजिए।
- (२) भारत के किसान आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
- (३) स्वतंत्रतापूर्व काल में महिला आंदोलन किन सुधारों के लिए संघर्ष कर रहे थे?

४. निम्न कथन सत्य अथवा असत्य; यह स्पष्ट कीजिए।

- (१) लोकतंत्र में आंदोलनों का बड़ा महत्त्व होता है।
- (२) आंदोलन को दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता नहीं होती।
- (३) उपभोक्ता आंदोलन अस्तित्व में आया।

उपक्रम

- (१) विविध सामाजिक आंदोलनों से संबंधित समाचारपत्र में छपे समाचारों को संकलित कीजिए।
- (२) अपने क्षेत्र की सार्वजनिक समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करनेवाले आंदोलन के कार्य का प्रतिवेदन लिखिए।
- (३) सब्जी अथवा अनाज खरीदते समय आपके साथ तौल में धोखाधड़ी हुई है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कैसे शिकायत करेंगे, उसका नमूना तैयार कीजिए।

